राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8994/2019

डाइकिन एयर कंडीशनिंग मजदूर यूनियन को अपने अध्यक्ष निवासी C/O रुक्मुदीन पुत्र नसरू खान, वी एंड पी सैदमपुर, तहसील गोविंदगढ़, जिला-अलवर (राजस्थान) के माध्यम से

---- अपीलार्थी

बनाम

1. मेसर्स डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसपी 2-12 से एसपी 2-15 और एसपी 2-24 से एसपी 2-27, रीको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मजराकाथ, तहसील नीमराना, जिला अलवर (राजस्थान) को प्रबंधक के माध्यम से।
2. अपर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन/संयुक्त श्रमायुक्त, राजस्थान सरकार, जोन कार्यालय पता-श्रम आयुक्त अधिकारी, श्रम भवन, एनबीसी गेट के सामने, हसनपुरा, जयपुर (राजस्थान)।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थियों की ओर से	:	श्री अमीन अली
प्रत्यर्थियों की ओर से	:	श्री वेयंकटेश गर्ग

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

आदेश आरक्षित करने की तारीख	:	12.09.2023
आदेश आरक्षित करने की तारीख	:	05.10.2023

रिपोर्टेबल

1. अपीलार्थी द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, अलवर द्वारा अपील

संख्या 01/2018 में पारित दिनांक 03.04.2019 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी यूनियन द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

<u>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतियां</u>

2. अपीलार्थी यूनियन के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी यूनियन ने भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (संक्षेप में '1926 का अधिनियम') के प्रावधानों के तहत अपने यूनियन के पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थी को अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेड यूनियन को 29.08.2018 को प्रमाणपत्र जारी करके पंजीकृत यूनियन के रूप में घोषित किया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 29.08.2018 के उक्त प्रमाणपत्र से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी कंपनी ने 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जो अभी भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा इस तरह के आवेदन के अनुसरण में 12.09.2018 को अपीलार्थी यूनियन को अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और अपीलार्थी यूनियन ने **एकल न्यायमूर्ति सिविल रिट याचिका संख्या 22454/2018** दायर करके इस न्यायालय के समक्ष नोटिस जारी करने के आदेश को चुनौती दी, जिसमें 03.10.2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और प्रतिवादियों को 12.09.2018 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त तथ्य को छिपाते हुए प्रत्यर्थी कंपनी ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक अपील प्रस्तुत की, जिसमें 29.08.2018 के उसी पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं थी, इसलिए इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी यूनियन ने उक्त अपील को अस्वीकार करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल ने दिनांक 03.04.2019 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दर्शाता है कि तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है। अधिवक्ता का कहना है कि तथ्यों का

कोई विवादित प्रश्न नहीं था और 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील की विचारणीयता के संबंध में केवल कानून का एक शुद्ध प्रश्न शामिल है, इसलिए ट्रिब्यूनल ने दिनांक 03.04.2019 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को खारिज करने में त्रुटि की है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

<u>प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी कंपनी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी यूनियन के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा अपील न केवल 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रस्तुत की गई थी, बल्कि इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में '1947 का अधिनियम') की धारा 9 (आई) की सहायता से भी प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के तहत अपील रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य है, इसलिए प्रतिवादियों ने 29.08.2018 के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने में कोई अवैधता नहीं की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी यूनियन को 1926 के अधिनियम की धारा 9 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन घोषित किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तथ्य और कानून के विवादित प्रश्न हैं और प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा दायर अपील कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी, इसलिए, ट्रिब्यूनल ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधिवक्ता का कहना है कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश सही और उचित है जिसे इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>विश्लेषण और तर्क</u>

4. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. बेशक, अपीलार्थी यूनियन ने श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष 1926 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अपने पंजीकरण के लिए आवेदन किया और अतिरिक्त रजिस्ट्रार-सह-संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर ने 29.08.2018 को एक आदेश पारित

किया और अपीलार्थी यूनियन को 'पंजीकृत यूनियन' के रूप में पंजीकृत किया।

6. दिनांक 29.08.2018 के पंजीकरण प्रमाणपत्र आदेश के उक्त अनुदान से व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी कंपनी ने रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के समक्ष उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसने 12.09.2018 को अपीलार्थी यूनियन को नोटिस जारी किया। दिनांक 12.09.2018 के उक्त नोटिस के खिलाफ, अपीलार्थी यूनियन ने इस न्यायालय के समक्ष एकल न्यायमूर्ति सिविल रिट याचिका संख्या 22454/2018 प्रस्तुत की, जिसमें 03.10.2018 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था और प्रतिवादियों को 12.09.2018 के नोटिस के अनुसरण में कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया गया था। तात्कालिक संदर्भ के लिए दिनांक 03.10.2018 के अंतरिम आदेश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

> "अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि नोटिस जारी किया जा चुका है। 12 सितंबर, 2018, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि धरना देने और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, नियोक्ता-कारखाने को उनके उत्पादन के संबंध में नुकसान हुआ है और यूनियन सदस्यों के जाली हस्ताक्षर प्रस्तुत करके पंजीकृत हुई है।
>
> अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित नोटिस में, यह आरोप लगाया गया है कि यूनियन की कथित गतिविधियों को ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 10 का उल्लंघन कहा गया है और इस तरह 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण पूछकर ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द करने का नोटिस दिया गया है।
>
> अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 10 के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकरण को कम से कम दो महीने पहले लिखित में नोटिस देना होगा और उसे यह भी संतुष्ट करना होगा कि पंजीकरण प्रदान करते समय क्या धोखाधड़ी या गलती की गई है।
>
> अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बहुत प्रयास करके और इस न्यायालय के

निर्देशों के बाद, पंजीकरण का प्रमाणपत्र 29 अगस्त, 2018 को जारी किया गया था और अब नियोक्ता द्वारा लगाए गए दबाव के कारण, पंजीकरण रद्द करने की पूरी कवायद शुरू की गई है।

प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, जिसका दो सप्ताह के भीतर जबाब दिया जाए।

यदि प्रार्थना की जाती है, तो नोटिस 'दस्ती' दिए जाएं।
इस बीच और अगले आदेश तक, प्रतिवादियों को 12 सितंबर, 2018 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कोई भी कार्यवाही करने से रोका जाता है।

7. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 29.08.2018 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के खिलाफ 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत दायर आवेदन रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के समक्ष न्यायाधीन है और यह इसके निर्णय के लिए लंबित है, लेकिन एकल न्यायमूर्ति CW संख्या 22454/2018 में इस न्यायालय द्वारा पारित 03.10.2018 के अंतरिम आदेश के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

8. फिर, प्रत्यर्थी कंपनी ने 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के साथ 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील दायर करके ट्रिब्यूनल के समक्ष 29.08.2018 के उसी पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती दी।

9. अपीलार्थी यूनियन ने उपरोक्त अपील को अस्वीकार करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (संक्षेप में, 'सीपीसी') के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है क्योंकि 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई भी अपील पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील केवल प्रमाणपत्र के पंजीकरण से इनकार, वापसी और रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य है। उक्त आवेदन में यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कानून के दो अलग-अलग मंचों के समक्ष दिनांक 29.08.2018 के एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र के खिलाफ दो समानांतर उपायों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए, उक्त अपील को कानून द्वारा प्रतिबंधित मानते हुए

अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। तात्कालिक संदर्भ के लिए 1926 के अधिनियम की धारा 11 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "**11. अपील-(1)** कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार करने या पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने से व्यथित है, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित किया जाए, अपील कर सकता है-
>
> क) जहां ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्यालय उच्च न्यायालय के प्रेसीडेंसी शहर [***] की सीमा के भीतर स्थित है, या
>
> [(कक) जहां प्रधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जो श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए, जैसा भी मामला हो;]
>
> ख) जहां प्रधान कार्यालय किसी क्षेत्र में स्थित है, ऐसे न्यायालय के लिए, जो मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय के अतिरिक्त या सहायक न्यायमूर्ति के न्यायालय से नीच नहीं है, जैसा कि [उपयुक्त सरकार] उस क्षेत्र के लिए इस संबंध में नियुक्त कर सकती है।
>
> (2) अपीलीय न्यायालय अपील को खारिज कर सकता है, या एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें रजिस्ट्रार को यूनियन को पंजीकृत करने और धारा 9 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है या आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है या प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और रजिस्ट्रार ऐसे आदेश का पालन करेगा।
>
> (3) उपधारा (1) के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए, अपीलीय न्यायालय, जहां तक हो सके, उसी प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय होती हैं और उसके पास हैं,

और वह निदेश दे सकेगा कि किसके द्वारा अपील की लागत का पूरा या कोई हिस्सा भुगतान किया जाएगा, और ऐसी लागतों को वसूल किया जाएगा जैसे कि उन्हें उक्त संहिता के तहत एक मुकदमे में दिया गया था।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किसी न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और उच्च न्यायालय को, ऐसी अपील के प्रयोजन के लिए, उप-धाराओं (2) और (3) के अधीन अपीलीय न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उन उप-धाराओं के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

10. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.04.2019 के आदेश के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें यह दर्शाता है कि तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हैं, जो उक्त अपील के निर्णय के समय इसके गुण-दोष पर तय किए जाएंगे।

11. अब इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न बना हुआ है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी कंपनी कानून के दो अलग-अलग मंचों के समक्ष दिनांक 29.08.2018 के एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र के खिलाफ दो समानांतर उपायों का लाभ उठा सकती है? क्या अपील को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है?

12. तथ्य इस बात पर विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी कंपनी ने कानून के दो अलग-अलग मंचों के समक्ष 29.08.2018 के उसी पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती दी है अर्थात 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष और ट्रिब्यूनल के समक्ष 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के साथ पठित 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील दायर की है।

13. 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के लिए पंजीकरण से इनकार करने के आदेश के खिलाफ या पंजीकरण के प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य है। यहां इस आदेश में न तो

रजिस्ट्रार ने अपीलार्थी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से इनकार किया और न ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द या वापस लिया गया। इसलिए, 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

14. प्रत्यर्थी कंपनी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील न केवल 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर की है, बल्कि 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) की सहायता के साथ 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **9(I). रजिस्ट्रार के आदेश से औद्योगिक न्यायाधिकरण में अपील।-** (1) रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, इस अध्याय के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, औद्योगिक न्यायाधिकरण में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है:
>
> बशर्ते कि औद्योगिक अधिकरण, पर्याप्त कारण के लिए, ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद की गई किसी भी अपील को स्वीकार कर सकता है।
>
> (2) औद्योगिक न्यायाधिकरण उप-धारा (1) के तहत अपील को स्वीकार कर सकता है यदि अपील के ज्ञापन के अवलोकन पर और इसके खिलाफ अपील किए गए निर्णय में पाया जाता है कि निर्णय कानून के विपरीत या अन्यथा गलत है।
>
> (3) अपील में औद्योगिक अधिकरण रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी भी आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरसन कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

15. 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के प्रावधानों का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यूनियनों के पंजीकरण के लिए 1947 के अधिनियम के अध्याय II B के तहत पारित रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य है। जबकि इस मामले में, अपीलार्थी यूनियन को 1947 के अधिनियम के अध्याय II बी के तहत कोई पंजीकरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपीलार्थी यूनियन को 1926 के अधिनियम की

धारा 9 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

16. जब 1926 के अधिनियम की धारा 11 और 1947 के अधिनियम की धारा 9 (I) के तहत कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, तो, निश्चित रूप से यह कानून के तहत एक रोक के बराबर है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

17. प्रत्यर्थी कंपनी बना-उपाय नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष चुनौती देकर दिनांक 29.08.2018 के पंजीकरण प्रमाणपत्र के खिलाफ उपाय का लाभ उठाया है।

18. प्रत्यर्थी कंपनी को एक ही विषय-वस्तु के संबंध में दो समानांतर उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अरुणिमा बरुआ बनाम भारत यूनियन (यूओआई) और अन्य 2007 (6) एससीसी 120** रिपोर्टित के मामले में कहा है कि "न्यायालय एक ही विषय-वस्तु के संबंध में एक पक्ष को दो समानांतर उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा।

19. **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने **जय सिंह बनाम भारत यूनियन मामले (1977) 1 एससीसी 1** रिपोर्टित एक मामले से निपटते हुए जिसमें अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, बाद में, उन्होंने उसी विषय-वस्तु को उठाते हुए एक मुकदमा दायर किया, न्यायालय ने कहा कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही समय में एक ही विषय-वस्तु के संबंध में दो समानांतर उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

20. **बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बॉम्बे बनाम गोकाक वोल्कार्ट लिमिटेड (1995) 1 एससीसी 642** रिपोर्टित में अपीलार्थी ने वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह की रिट विचार योग्य नहीं है।

21. इस प्रकार, कानून के उपर्युक्त त्याग से, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत के निवारण के लिए मंच चुनने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे एक ही राहत के लिए एक ही विषय-वस्तु के संबंध में दो मंचों को चुनने की अनुमति नहीं दी जा

सकती है। यदि समानांतर कार्यवाही की अनुमति दी जाती है, तो वे फोरम शॉपिंग को जन्म दे सकते हैं, जिसमें एक पक्ष जिसने रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के समक्ष 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत आवेदन दायर किया था और अंतरिम राहत प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, उसके समक्ष उपाय को छोड़ देता है और उसी कारण से ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का प्रयास करता है। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

22. उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत के प्रकाश में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी कंपनी को दिनांक 29.08.2018 के पंजीकरण प्रमाणपत्र के एक ही विषय के संबंध में दो समानांतर उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात एक अधिनियम 1926 की धारा 11 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के माध्यम से और दूसरा रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के समक्ष 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत आवेदन के माध्यम से।

<u>निष्कर्ष :</u>

23. उपर्युक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 03.04.2019 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और 1926 के अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को "सुनवाई योग्य नहीं" के रूप में खारिज कर दिया गया है। हालांकि, प्रत्यर्थी कंपनी के लिए 1926 के अधिनियम की धारा 10 के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने का विकल्प खुला है जो रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

24. पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन इस न्यायालय द्वारा ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना दोनों पक्षों को सुनने के बाद लंबित आवेदन पर अपनी गुणागुण के आधार पर फैसला करेगा।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

KuD/49/Pcg/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।